



Sardar Vallabhbhai Patel

COMMUNIST NATION PARTY- INDIA

कम्यूनिस्ट नेशन पार्टी - (भारत)

કોમ્યુનિસ્ટ નેશન પાર્ટી-ભારત

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷ- ಭಾರತ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേഷൻ പാർട്ടി-ഇന്ത്യ

کمیونسٹ نیشن پارٹی - (انڈیا)

Regd./ H.O.-Shop No. 5, Ground Floor, Building No. 5, C.T.S. No. 9A, 9A/1 to 57, 123A & 123B, Sunshine SRA Co-operative Housing Society Ltd., Malkani Estate, Opp. Times of India, Malad (E), Mumbai- 400 097

Correspo.Add.-Shop No. 3, S. 341, Building Opp. Nanda Deep Garden, B.K.C. Junction, B. K. C. Junction, B.KC Road, Kalanagar, Bandra (E), Mumbai- 400 051
✉ communistonationparty@gmail.com
+91-93212 11753 / +91-98708 44521

Website: <https://www.cnp-i.org/>



Adv. A. A. Siddiquie
CNP-I: Chief Convenor

CNP-I: Convenors



Dalvi Dayanand



Adv. Chowdhari Moin



Adv. Suchi Waghani



Shaikh Suhail



Ansari Umar



Md. Sharif



Sayyed Salman



Shetty Vishwanath



Pandit Vinay Mishra



Adv. Amit Vashikar



Nausherwan Baluch



Alzira Variava



Prabhakar Kamble



Shaikh Azam Ali



Adv. Syed Mukhtar A. Rizvi

कम्युनिस्ट नेशन पार्टी (इंडिया) सीएनपी-आई मैनिफेस्टो

भाग-ए

पार्टी संविधान के चार स्तंभों-धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, संघवाद और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, समाज के अन्य उपेक्षित वर्ग, जैन, ईसाई, मुस्लिम समुदाय, महिलाओं, युवाओं और छात्रों को N.D. A. OR INDIA के नेतृत्व वाली सरकारों के हाथों पीड़ित होते हुए देखा जा रहा है, (सीएनपी-आई) सभी के बावजूद जन-समर्थक नीतियों और सांप्रदायिक सद्भाव की एक किरण के रूप में उभरते हैं।

यह भारत के लोगों के लिए एक स्पष्ट समझ के साथ है कि यह प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है कि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता, और उन सभी के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना और एनडीए/भारत के उद्देश्य और नीति को हराना सुनिश्चित करें।

सी. एन. पी. (आई) निम्नलिखित प्रतिज्ञा करता है:

1. राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल की एक छत के नीचे सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराकर जन-समर्थक नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र/राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना करना, समाज के गरीब वर्ग के लिए निजी अस्पतालों में 20% से 40% आरक्षण और/या बिना किसी लागत के सरकारी अस्पताल द्वारा रोगी को संदर्भित करने की सुविधा।
2. सरकार और/या उसके राजनीतिक सदस्य के कहने पर किसी विशेष, वर्ग या समुदाय को लक्षित करके कोई दुर्भावनापूर्ण अभियोजन नहीं होगा, यदि कोई प्राधिकरण ऐसी

गतिविधि का समर्थन करने में लिप्त पाया जाता है तो उन पर भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 311 के तहत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

3. कोई NEET और JEE परीक्षा नहीं, सभी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज राज्य/केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होंगे। एक प्रवेश सुरक्षित (10+2) पैटर्न के आधार पर होगा, निजी मेडिकल कॉलेज और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में संबंधित राज्य के लिए 75% आरक्षण होना चाहिए और शुल्क सरकारी कॉलेज के समान होगा।
4. कृषि, व्यापार उद्योग में राज्य की सह-भागीदारी होगी, 40:60 प्रतिशत के अनुपात में एक उद्यमी होगा, बिना किसी ब्याज के इसे बढ़ावा देने के लिए ऋण की सुविधा होगी।
5. लोक रोजगार में समान नागरिक संहिता होगी और सरकारी अनुदान सुविधा में कृषकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, ऑटो रिक्शा चालकों, टैक्सी चालकों, औद्योगिक मजदूरों, घरेलू नौकरानियों, छोटे व्यापारियों, उद्यमियों, रेहड़ी-पटरी वालों और समाज के उपेक्षित कमजोर वर्ग आदि के लिए मुफ्त आवास होगा।
6. 10 + 2 परीक्षा पैटर्न और एक I.T.I तक मुफ्त शिक्षा होगी। समाज के कमजोर वर्ग के लिए पाठ्यक्रम और सामान्य श्रेणी के छात्र के लिए शुल्क की पूर्ण छूट।
7. महिलाओं के विशेष सुरक्षा बल का गठन करके कार्यस्थल, शिक्षा संस्थान और जहां भी इसकी आवश्यकता हो, वहां महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा प्रदान करना।
8. महिलाओं के लिए मुफ्त स्वच्छता सुविधा और आवास पर कॉल पर मुफ्त चिकित्सा जांच। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के साथ मोबाइल मेडिकल वैन शामिल है।
9. सरकारी कार्यालयों के आगंतुकों और सुरक्षा सुविधा के साथ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यमियों के लिए अनिवार्य मुफ्त सार्वजनिक पार्किंग।
10. महानगर के साथ-साथ शहर में दस मंजिला से अधिक की प्रत्येक इमारत में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दस से बीस बिस्तरों वाली चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, जिसका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में किया जाएगा।
11. प्रत्येक परिवार के लिए सब्सिडी दरों पर आवश्यक रसोई गैस रुपये के बीच सब्सिडी दर पर होगी। 200 से रु. 500 प्रति घरेलू सिलेंडर और या उसके बराबर खपत।
12. कॉर्पोरेटर, विधायक/एमएलसी, सांसद (लोकसभा) और सांसद (राज्यसभा) के लिए कई पेंशन नीतियों को समाप्त करने के लिए राज्यों/केंद्र सरकारों के राजकोषीय घाटे के आधार पर एकल पेंशन नीति होगी।
13. दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन-यदि राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार किसी भी परिस्थिति में पार्टी के बैनर तले चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़ देता है तो निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी और नियम में दी गई प्रक्रिया का पालन करके सभी पिछले और भविष्य के लाभ को जब्त कर लिया जाएगा।

14. राजनेताओं और समाज और या किसी व्यक्ति को किसी भी शीर्ष के तहत दिए गए सरकारी भूमि पट्टे को रद्द कर दिया जाएगा, जिसे या तो बेघरों के लिए विकसित किया जाएगा और समाज के विभिन्न वर्गों को पुनर्स्थापित किया जाएगा।
15. विधायक/एमएलसी, सांसद (लोकसभा) और सांसद (राज्यसभा) के लिए एक से अधिक सुरक्षा गार्ड नहीं होंगे-कैबिनेट मंत्री चार से अधिक सुरक्षा व्यक्तिगत गार्ड के हकदार नहीं होंगे। यदि राज्य की विधानसभा और संसद का कोई सदस्य अधिक सुरक्षा चाहता है तो उसे सुरक्षा शुल्क देना होगा।
16. अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कोई पुनर्नियुक्ति नीति नहीं है।
17. J.M.F.C , जिला शहर सिविल और सत्र न्यायालय स्तर, उच्च न्यायालय स्तर और उच्चतम न्यायालय स्तर पर Magistrate/Judges की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली होगी, जो उनके द्वारा किए गए कार्य-ग्राहक की संतुष्टि और संबंधित वकीलों के परामर्श के आधार पर होगी। इच्छा के अधीन सभी अधिवक्ताओं को कानून और तथ्यों को समझने के अधीन 2 से 5 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्र के लिए अपनी सेवा करने का अवसर मिलेगा।
18. समाज को न्याय का प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जिला शहर सिविल और सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और निर्णयों की उनके संबंधित स्तर पर जांच करने के लिए बार के सदस्यों और जनता के सदस्यों की एक समिति होगी।
19. संबंधित चैरिटी कमिश्नर के साथ पंजीकृत भाषाई अल्पसंख्यक की संपत्तियों के संरक्षण के लिए विशेष अधिनियम। i.e स्कूल, कॉलेज और अस्पताल
20. धार्मिक संस्थानों यानी दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसों की आय के स्रोत के लिए अन्य वक्फ संपत्तियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन।
21. शिया समुदायों के लिए स्वतंत्र वक्फ बोर्ड, उपेक्षित और/या कम मुस्लिम कब्रिस्तान को बनाए रखने के लिए समय-समय पर अनुदान।
22. कुरान और अन्य भाषाई भाषाओं को पढ़ाने के लिए संबंधित राज्य/केंद्र सरकार के अनुदान के तहत मदरसों को बढ़ावा देना और स्थापित करना।
23. संबंधित राज्य/केंद्र सरकार/संस्थाओं के अनुदान के तहत वेदों, पुराणों, उपनिषदों के शिक्षण के लिए हिंदू मठ का संवर्धन और स्थापना।
24. 1:5 के अनुपात में वृक्षों के अनिवार्य रोपण और स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के लिए वन संरक्षण का प्रावधान।
25. विलुप्त वन्यजीवों का संरक्षण।
26. कृत्रिम झील परियोजना की स्थापना करके पानी की कमी को पूरा करने का प्रावधान।

27. राज्य C.M से परिवार के बुजुर्ग गरीब सदस्य के लिए हज और उमराह का प्रावधान। समेकित निधियाँ।
28. सभी धामों के दर्शन, श्री राम लाला के दर्शन स्थल, अमरनाथ यात्रा आदि का प्रावधान। राज्य C.M ki समेकित निधियाँ से परिवार के बुजुर्ग गरीब सदस्य के लिए। ।
29. संबंधित राज्य सरकार के विशेष बजट द्वारा आवधिक आधार पर सभी मस्जिदों, धार्मिक स्थलों, कब्रिस्तानों और मदरसों की बहाली।
30. महाराष्ट्र राज्य, बिहार राज्य, झारखंड राज्य, मध्य प्रदेश राज्य को विशेष दर्जा, जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न, रसोई गैस, जीवन रक्षक दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं को सब्सिडी दर के साथ-साथ बिना किसी कर देयता के बनाया जाएगा।
31. महाराष्ट्र राज्य, बिहार राज्य, झारखंड राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, हरियाणा राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को विनियमित करने का प्रावधान और मस्जिदों, तीर्थ, कब्रिस्तान और मदरसों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा।
32. महाराष्ट्र राज्य, बिहार राज्य, झारखंड राज्य, मध्य प्रदेश राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों में मस्जिदों के इमाम, मोअज्जिन, दरगाह के खादिम, कब्रिस्तान के प्रबंधक और मदरसों के मदरसे को वेतन का प्रावधान।
33. महाराष्ट्र राज्य, बिहार राज्य, झारखंड राज्य, मध्य प्रदेश राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों में सभी मंदिरों के पुजारी, मठ के शिक्षक को उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान के साथ वेतन का प्रावधान।
34. महाराष्ट्र राज्य, बिहार राज्य, झारखंड राज्य, मध्य प्रदेश राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों में सभी गुरुद्वारों और चर्चों के पुजारी को उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान के साथ वेतन का प्रावधान
35. सभी मंदिरों के पुजारी, मठ के शिक्षक को वेतन का प्रावधान। महाराष्ट्र राज्य, बिहार राज्य, झारखंड राज्य, मध्य प्रदेश राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों में उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान के साथ।
36. आवश्यक संशोधन के साथ अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम और सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन ।
37. महाराष्ट्र राज्य में स्ट्रीट वेंडर (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 का कार्यान्वयन।

भाग-ए में घोषणापत्र मुख्य वर्तमान मुद्दों पर केंद्रित है। भाग-बी में, घोषणापत्र भारत के लोगों के कल्याण के लिए वैकल्पिक नीतियों के लिए सीएनपी (आई) के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

भाग-बी वैकल्पिक लक्ष्यों की मुख्य बातें

इस तरह के वैकल्पिक लक्ष्यों/उद्देश्यों की मुख्य विशेषताएं, जिन्हें सीएनपी (आई) को लागू करने का संकल्प लिया गया है, वे हैं:

1. भारत के संविधान 1950 में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना।
2. किसानों को अपनी उपज को न्यूनतम मानक मूल्य पर बेचने का अधिकार देने के लिए एक नीति तैयार करना जो उत्पादन की कुल लागत से कम से कम 35 प्रतिशत अधिक हो।
3. श्रमिकों के लिए मानक न्यूनतम मजदूरी के लिए नीति रुपये से कम नहीं। 16, 000 प्रति माह; मानक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार।
4. प्रति व्यक्ति 15 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं, चावल की दाल, चीनी/गुड़) और प्रति व्यक्ति 10 से 15 किलोग्राम रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली।
5. कोई निजी बीमा डोमेन स्वास्थ्य देखभाल नहीं; स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार का बीमा करना स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।
6. संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए कानून को जनगणना और परिसीमन से जोड़े बिना; महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए तत्काल व्यापक कदम।
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समाप्त किया जाएगा-सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का विस्तार-गुणवत्ता उन्नयन के साथ; शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत होना; शिक्षा प्रणाली के सांप्रदायिकरण को समाप्त करना और इसके लोकतांत्रिक चरित्र को सुनिश्चित करना।
8. भारत के संविधान, 1950 के तहत काम करने का अधिकार; बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान।
9. न्यूनतम मासिक पेंशन के साथ वृद्धावस्था पेंशन जो न्यूनतम मजदूरी के आधे से कम नहीं है, या रु। सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह, जो भी अधिक हो।

10. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण को रोकना और रक्षा, ऊर्जा, रेलवे और बुनियादी सेवाओं में निजीकरण को निरस्त करना।
11. शिक्षा और निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधा।
12. अति-अमीरों के लिए संपत्ति कर की बहाली और रुपये मूल्य के लिए विरासत कर लागू करना। 5, 00, 00,000/- (केवल पांच करोड़ रुपये; पूंजीपति के खिलाफ दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की बहाली।
13. निर्वाचन व्यय को कम करने के लिए मतदान का अधिकार रखने वाले नागरिक और नागरिक (निर्धारित किए जाने वाले मानदंड) वाले अनुलग्नकों को विभाजित करके निर्वाचन प्रणाली में सुधार।

लोकतंत्र की सुरक्षा का प्रभाव

सी. एन. पी. (आई) यह सुनिश्चित करेगी कि:

संविधान, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बनाया जाए।

इसकी आवश्यकता है:

1. उच्च न्यायपालिका, भारत के चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों जैसे संस्थानों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की रक्षा के उपाय।
2. गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को निरस्त करना (AFSPA).
3. दुरुपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त कानून के साथ पीएमएलए को निरस्त करना। ईडी को अपनी कानून-प्रवर्तन शक्तियों से वंचित किया जाना चाहिए।
4. भारतीय विधि आयोग द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, बी. एन. एस. एस. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के संशोधन और/या अलोकतांत्रिक प्रावधानों को समाप्त करने और मजिस्ट्रेट की शक्ति को कम करने वाली पुलिस शक्तियों को बढ़ाने के लिए निरसन और/या पुनः विचार करना असहमति के अधिकार की रक्षा करता है।
5. सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आधार और बायोमेट्रिक्स के अनिवार्य उपयोग को समाप्त करना।
6. यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की समीक्षा।
7. किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए संसदीय अनुमोदन को अनिवार्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा।

सुरक्षा का संरक्षण

सीएनपी (आई) धर्म और राजनीति को अलग करने और इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी विधायी उपायों को पारित करने और लागू करने के लिए खड़ा है। सांप्रदायिक हिंसा से सख्ती से निपटा जाए। राज्य द्वारा सभी क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कसंगतता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सी. एन. पी. (आई) निम्नलिखित दिशा में काम करेगी:

1. नागरिकता संशोधन अधिनियम को स्कैप किया जाएगा।
2. अल्पसंख्यकों को लक्षित करने वाले राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए।
3. कोई भी लोक अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबद्ध होने की अनुमति नहीं देता है, यदि उसे तुरंत हटा दिया जाता है और सेवानिवृत्ति के बाद अन्य लाभ विभागीय जांच का विषय होंगे।
4. लिंग के खिलाफ तुरंत कानून बनाने, सभी अवैध निजी सेनाओं और विभिन्न "सेनाओं" जैसे तथाकथित सतर्कता समूहों पर प्रतिबंध लगाने के साथ जो गोरक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं और सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं। सांप्रदायिक घृणा फैलाने में शामिल संगठनों और संस्थानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उचित कानूनी उपायों को लागू करना।
5. सांप्रदायिक हिंसा के अपराधियों के लिए उनकी सार्वजनिक या आधिकारिक स्थिति की परवाह किए बिना कानून का अधिनियमन।

आर्थिक आदर्श नीतियाँ

सी. एन. पी. (आई) आर्थिक नीतियों के लिए काम करेगी।

1. योजना आयोग की बहाली।
2. मांग बढ़ाने के लिए लोगों के हाथों में रोजगार और धन पैदा करने की दिशा में रोजगार सृजन के विकास के लिए सर्वहारा सिद्धांत का परिचय।
3. पूंजीवादी, निगमित लाभ और विलासिता वस्तुओं के संसाधनों पर कर आधार को बढ़ाना।
4. कृषि उत्पादन, अनुसंधान और जैविक खेती की सिंचाई में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि।
5. भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा-बिजली, सार्वजनिक परिवहन, बंदरगाह, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक अस्पताल प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निवेश के लिए पर्याप्त संसाधनों का वितरण।
6. बड़े पैमाने पर उपभोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना न कि अस्थिर विलासिता वस्तुओं के लिए।

7. बीज, उर्वरक, बिजली/डीजल जैसे कृषि आदानों के लिए वैधानिक प्रावधान और सब्सिडी।
8. अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहन के लिए वैधानिक प्रावधान और छोटे और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विशेष पहल जो बहुत अधिक रोजगार प्रदान करते हैं।
9. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करना और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए राजकोषीय अभ्यास में एक बाध्यकारी बाधा के रूप में सामाजिक क्षेत्र के खर्च के लिए न्यूनतम तल निर्धारित करना।
10. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी इक्विटी को और कमजोर करने की रोकथाम और प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए बैंकिंग और बीमा में सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना।
11. वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामक प्राधिकरणों के लिए प्रावधान अनिवार्य रूप से संसद और विधायी निरीक्षण के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
12. राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख आर्थिक निर्णयों में राज्य सरकारों की अनिवार्य भागीदारी, राज्यों की निर्णय लेने की शक्तियों को बहाल करना और राज्यों द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए अधिक राजकोषीय लचीलेपन की अनुमति देना।

संसाधनों का पुनर्स्थापन

सीएनपी (आई) करेगा:

1. प्रभावी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की बहाली और प्रतिभूति लेनदेन कर में वृद्धि।
2. कानूनी कार्रवाई से बचने और धन की वसूली के लिए भारत से भाग गए बड़े पैमाने पर ऋण चूककर्ताओं की अभिरक्षा सुनिश्चित करें।
3. अमीरों के लिए संपत्ति कर की बहाली और विरासत कर लागू करना।
4. वैधानिक दरों को बढ़ाकर कॉरपोरेट लाभ कर में संशोधन ताकि प्रभावी कर दरें कम न हों, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हो।
5. भारत में अंतर्निहित परिसंपत्तियों के साथ विदेशी कंपनी में शेयरों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से पूंजीगत लाभ का अनिवार्य कराधान।
6. हमारे देश के संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों का सम्मान करते हुए उनके साथ संसाधनों को साझा करके अनिवार्य जीएसटी में बदलाव किया जाना चाहिए।

वित्तीय क्षेत्र के लिए विनियमन

CNP (I) का अर्थ है:

1. राज्य और लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के प्रभुत्व को विनियमित करने के लिए नीति के लिए एक सख्त वित्तीय विनियमन। राष्ट्रीय आय की तुलना में कुल वित्तीय देनदारियों को कम करने के लिए नीतियां विकसित करें।
2. द्विपक्षीय स्वेप लाइन (बीएसएल) और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से गैर-डॉलर व्यापार समझौतों के विस्तार और समेकन के लिए विनियमन; ब्रिक्स +, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) आदि जैसे क्षेत्रीय समूहों के बीच वित्तीय एकजुटता और समन्वय को मजबूत करना।
3. क्रिप्टो मुद्राओं पर नियम और दिशानिर्देश।
4. पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए विनियमन और वित्त पूंजी के प्रवाह और बहिर्वाह पर प्रतिबंधों को बहाल करना।
5. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को सहभागी नोटों का उपयोग करने और अत्यधिक जोखिम लेने और वित्तीय बाजार की अस्थिरता को कम करने के लिए सट्टा वित्तीय साधनों को हतोत्साहित करने का विनियमन।
6. रिजर्व और आरबीआई की स्वायत्तता के लिए अधिनियम; आरबीआई के शासन और नियामक तंत्र को मजबूत करना।
7. नए निजी बैंक लाइसेंस जारी करने, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2012 की समीक्षा करने और विदेशी बैंकों को भारतीय बैंकों का अधिग्रहण करने से रोकने पर प्रतिबंध।
8. विनियमन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को मजबूत करना कोई पीएसबी निजीकरण नहीं; पीएसबी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को कम करने के लिए बैंकिंग अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों को उलटना; प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण के तहत निजी बैंकों सहित; बैंकों के जोखिम को कम करने के लिए कुशल पूंजी विनियमन शुरू करना।
9. बड़े उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर बढ़ाने की नीति; छोटे ऋणों के लिए ब्याज दर को कम करना; बचत खातों और खुदरा जमाओं के लिए ब्याज दर को बढ़ाना सामान्य खुदरा और वित्तीय समावेशन ग्राहकों के लिए सेवा शुल्क को कम करना।
10. बेनामी संपत्तियों सहित कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की संपत्तियों को जब्त करके सभी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की वसूली के लिए विनियमन; जानबूझकर चूक करने वालों को दंडित करने और वसूली के लिए आपराधिक कानूनों में संशोधन; दिवाला और दिवालियापन संहिता को वापस लेना (IBC).

11. आई. डेटा संप्रभुता बनाए रखते हुए फिन-टेक क्षेत्र में अमेज़ॅन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों के प्रभुत्व को विनियमित करना।
12. सूक्ष्म उधारकर्ताओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए निजी सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एम. एफ. आई.) पर विनियमन। निजी एम. एफ. आई. के लिए पीएसबी वित्त पोषण बंद करें; वाणिज्यिक संस्थानों को बैंकों से अलग करना।
13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015 पर पुनर्विचार
14. बैंकिंग विनियमन-1949 संशोधन अधिनियम, 2020 को निरस्त करना; आरबीआई की देखरेख में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को जमा एकत्र करने की अनुमति देना; लोगों को ब्याज वाले ऋण के चंगुल से बचाने के लिए सहकारी बैंकों को मजबूत करना; और सहकारी बैंकों को आयकर से छूट देना।
15. एलआईसी से सरकारी शेयरों को कम करने पर रोक; जीवन, चिकित्सा और सामान्य बीमा पर जीएसटी को हटाना; सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए समेकित किया जाएगा।
16. कर पनाहगाहों में पूंजी का विनियमन प्रवाह; उचित कराधान सुनिश्चित करने के लिए दोहरे कर परिहार समझौतों में खामियों को दूर करना।
17. जमाओं की सुरक्षा, पोंजी योजना के मालिकों की संपत्तियों को जब्त करने और प्रभावित जमाकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए चिट फंड कानून को मजबूत करने के लिए विनियमन।
18. वित्तीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रतिबंधित करना।

व्यापार से संबंधित मुद्दे

CNP (I) का अर्थ है:

1. भारतीय हितों की रक्षा के लिए विनियमन और भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने और "व्यापार युद्ध" छेड़ने के लिए अमेरिकी कदमों का विरोध करना।
2. मात्रात्मक प्रतिबंधों सहित छोटे और सीमांत किसानों की सुरक्षा के उपाय।
3. जीएटीएस से बाहर स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को विनियमित करना; ट्रिप्स समझौते की अनिवार्य समीक्षा।
4. यूरोपीय संघ के साथ मौजूदा शर्तों पर एफटीए के लिए बातचीत के साथ मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का पुनरुद्धार।

संघवाद को बढ़ावा देना

CNP (I) का अर्थ है:

1. एक उपयुक्त प्रावधान के साथ अनुच्छेद 356 का निरसन और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए अनुच्छेद 355 में संशोधन।
2. राज्यपालों की भूमिका और पद की प्रक्रिया को विनियमित करना। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पैनल से की जाती है।
3. राज्यों को केंद्रीय करों के संग्रह के कुल पूल का 50 प्रतिशत अनिवार्य रूप से वितरित करना; राज्यों के साथ अधिभार और उपकर का बंटवारा।
4. राज्यों को निधियों के साथ एक राज्य विषय के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के हस्तांतरण का प्रावधान।
5. केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी अंतर-राज्य परिषद के निर्णय लेने के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग करना; राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया जाना; योजना आयोग को बहाल करना, जो एनडीसी के कार्यकारी विंग के रूप में कार्य करना है।
6. सकल घरेलू उत्पाद के लिए स्थानीय स्व-सरकारी व्यय के न्यूनतम स्तर के लिए एक लक्ष्य की अनिवार्य स्थापना; स्थानीय निकायों को हस्तांतरित धन को राज्य सरकारों के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

इन्फ्रास्ट्रक्चर

CNP (I) का अर्थ है:

1. आई. लोक उन्मुख योजना और सर्वहारा वर्ग के विकास को प्राथमिकता।
2. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) स्टाल को निरस्त करना और एनएमपी के विभिन्न मार्गों के माध्यम से निजी निगमों को ब्राउनफील्ड बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक उपहार को उलटना; निजीकरण को निरस्त करना और विनिवेश, पीपीपी और विभिन्न अन्य मार्गों के माध्यम से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को कमजोर करना।
3. राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण पाइपलाइन (एन. एल. एम. पी.) को निरस्त/पुनर्स्थापित करना निजी निगमों के हाथों में अद्वितीय किराया संग्रह क्षमता के साथ विशाल, सन्निहित भूमि पार्सल के संचय को रोकता है।
4. सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (बिजली, संचार, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे आदि) के निर्माण, संचालन, रखरखाव और राजस्व प्राप्ति को बढ़ावा देना। केवल सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से।
5. निजी कंपनियों को आवंटित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) को याद करना; सार्वजनिक राजमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों, गैस या बिजली लाइनों

आदि से निजी ओ एंड एम एजेंसियों द्वारा राजस्व निकासी (टोल, टिकट या अन्य शुल्क) को समाप्त करना, जो लोगों पर गंभीर रूप से बोझ डालते हैं; इन कार्यों में सार्वजनिक उद्यमों को मजबूत करना।

6. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा भंडारण और भविष्य के अन्य सभी ऊर्जा संसाधनों में निजी एकाधिकार को बढ़ावा देने और स्थापित करने वाली नीतियों को याद करना; हमारे देश की ऊर्जा संप्रभुता की रक्षा के लिए नवीकरणीय क्षेत्र में सरकार की निर्णायक हिस्सेदारी स्थापित करना; जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में संक्रमण की प्रक्रिया में प्रभावित समुदायों (विशेष रूप से कोयला श्रमिकों) की आजीविका और आर्थिक दायरे की रक्षा के लिए एक मजबूत सहभागी तंत्र तैयार करना।
7. रियायती दरों के माध्यम से सस्ती बिजली का प्रावधान सुनिश्चित करना; बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को रद्द करना; निजी संस्थाओं द्वारा टीओटीईएक्स मॉडल के तहत प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग का निलंबन; सार्वजनिक बिजली क्षेत्र के निजीकरण को उलटना; सभी असंबद्ध बिजली उपयोगिताओं की पुनः स्थापना; बिजली क्षेत्र के भीतर वर्तमान निजी लाइसेंसें को रद्द करना; आभासी निजी बिजली बाजार और गतिशील मूल्य निर्धारण का उन्मूलन।
8. महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के भीतर निजी एकाधिकार को प्रतिबंधित करना, जैसे कि बंदरगाहों और बिजली में शामिल समूह, साथ ही डेटा भंडारण और प्रबंधन; भारतीय नागरिकों के संप्रभु डेटा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा बुनियादी ढांचे की स्थापना, और निजी उद्यमों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के अप्रतिबंधित उपयोग को विनियमित करने के लिए नीतियों को लागू करना।
9. दूरसंचार विधेयक, 2023 को निरस्त करने का उद्देश्य निजी-समर्थक दूरसंचार नीतियों को उलटना, सार्वजनिक क्षेत्र की पहलों के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार और इंटरनेट की पहुंच को बढ़ावा देना है। इसमें समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करके और 4जी और 5जी सेवाओं की तैनाती में तेजी लाकर बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार संस्थाओं को मजबूत करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार पर जोर देता है और संचार उपकरणों के निर्माण में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।
10. सुरक्षा, गति और पहुंच में सुधार के लिए रेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण सरकारी वित्त पोषण का निर्देश दिया जाएगा। इसमें रेलवे स्टेशनों के निजीकरण को उलटना, समर्पित माल गलियारों की स्थापना करना और माल और यात्री ट्रेन सेवाओं दोनों को अनुकूलित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, किफायती और सेवाओं के उन्नयन को सुनिश्चित करते हुए घरेलू प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रेलवे रेक और उपकरणों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
11. मकान मालिक बंदरगाह मॉडल का उन्मूलन; कार्गो संचालन के लिए नई लागू स्टीवडोरिंग नीति को रद्द करना; सार्वजनिक-निजी भागीदारी ढांचे के तहत महत्वपूर्ण बंदरगाह अस्पतालों की आउटसोर्सिंग को रद्द करना। प्रमुख बंदरगाहों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करें।

12. अनाज और फलों और सब्जियों जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों से परे फसलों की खरीद का समर्थन करने के लिए गोदाम निगम के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना; गोदाम निगम की सुविधाओं को निजी एकाधिकार को पट्टे पर देना बंद करना।

उद्योग

CNP (I) का अर्थ है:

1. विभिन्न प्रशासनिक निर्देशों और दिशानिर्देशों के माध्यम से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को नष्ट करने और कमजोर करने की हानिकारक नीतियों को उलटना; डीआईपीएम द्वारा शुरू की गई पीएसयू की सभी निजीकरण पहलों को रोकना।
2. सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना, विशेष रूप से आवश्यक और रणनीतिक क्षेत्रों में, लेवी के महत्वपूर्ण बोझ को कम करके, आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए मुनाफे के प्रभावी पुनर्निवेश को सक्षम करना, संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, नई पूंजी और उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ कमजोर सार्वजनिक उपक्रमों को सहायता प्रदान करना, सभी आयात दायित्वों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की गारंटी देना और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बीच अधिक स्वायत्तता, दक्षता और सहयोग को बढ़ावा देना।
3. एक व्यापक दीर्घकालिक औद्योगिक नीति को लागू करना जो उच्च रोजगार-से-निवेश अनुपात प्राप्त करने के लिए निवेश रणनीतियों और समझौता ज्ञापन (एमओयू) की शर्तों को फिर से परिभाषित करता है; समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनकी पूरक भूमिकाओं को प्रोत्साहित करके सेवाओं और विनिर्माण के बीच की खाई को पाटना।
4. एक सख्त निर्यात-आयात-निवेश नीति के माध्यम से वैश्विक उत्पादन नेटवर्क के हमारे घरेलू क्षेत्रों के भीतर मूल्य संवर्धन और विनियोग में वृद्धि सुनिश्चित करना; बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) और अंतरराष्ट्रीय निगमों की मूल्य श्रृंखलाओं में सख्त श्रम मानकों के अनुपालन को लागू करना। (TNCs).
5. इक्विटी निवेश और क्रॉस-ओनरशिप पर एक सीमा स्थापित करके गैर-वित्तीय संस्थाओं पर वित्तीय फर्मों के बढ़ते प्रभाव को सीमित करना; गैर-वित्तीय कंपनियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से सक्रिय ऋण नीतियों को बढ़ावा देना; स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना; और एकाधिकार गठन और गुटबंदी के खिलाफ सतर्क उपायों को लागू करना।
6. जूट मिलों, बागानों, कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प और कॉयर जैसे श्रम प्रधान पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करना; घरेलू उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सख्त नीतियां विकसित करना; और भारतीय उत्पादों के लिए घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों के विकास को बढ़ावा देना।

7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एमएसएमई) को उचित प्रोत्साहन प्रदान करके, बुनियादी ढांचे की सहायता बढ़ाकर और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पर्याप्त ऋण पहुंच सुनिश्चित करके श्रम प्रधान उद्योगों में बढ़ावा देना; एमएसएमई क्षेत्र में निजी सूक्ष्म वित्त के प्रवेश पर सख्त नियमों को लागू करने वाली क्लस्टर विकास परियोजनाओं (सीडीपी) के लिए धन बढ़ाना; और संकटग्रस्त कम आय वाले समूहों के लिए ऋण माफ करना।
8. स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और सहकारी समितियों जैसे सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करके उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक सहायक ढांचा विकसित करना; इन संस्थाओं, विशेष रूप से घर-आधारित और पारंपरिक उद्योगों में लगे लोगों के लिए सब्सिडी वाले ऋणों तक पहुंच बढ़ाना; और सहकारी समितियों और संघों के विकास को बढ़ावा देना।
9. खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाना; एक लाइसेंसिंग ढांचे के माध्यम से ई-कॉमर्स और स्थानीय कॉर्पोरेट खुदरा विक्रेताओं के लिए नियम स्थापित करना; और छोटे उत्पादकों और निर्माताओं का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा संचालित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करना।
10. अमेज़न, उबर और ज़ोमैटो जैसे वैश्विक निगमों के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवाओं को लागू करना; बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के भीतर स्थानीय स्टार्ट-अप और सहकारी समितियों के लिए व्यापक सरकारी समर्थन और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
11. श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए टियर-II और टियर-III शहरों में अधिक आईटी नौकरियों और तकनीकी प्रगति को आकर्षित करने के लिए सक्रिय उपाय करना; आईटी हार्डवेयर और घटकों का उत्पादन बढ़ाना; सरकारी विभागों और उनकी सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली आईटी फर्मों की स्थापना; और एल्गोरिदम, एआई/एमएल और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों की देखरेख के लिए नियम तैयार करना ताकि उनके लाभ जनता के लिए सुलभ हों।
12. कर लाभों को दूर करने और अनियमित भूमि उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एस. ई. जेड. अधिनियम और इससे जुड़े नियमों को धीरे-धीरे संशोधित करना; सभी एस. ई. जेड. में श्रम कानूनों का कठोर प्रवर्तन सुनिश्चित करना।
13. दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की पूरी तरह से समीक्षा करना, उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक धन के डायवर्जन को सुविधाजनक बनाने वाली कार्रवाइयों का विरोध करना; बड़े निजी उद्यमों के लिए बिना शर्त ऋण माफी के खिलाफ सख्त नीतियों को लागू करना।
14. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन को निरस्त करना जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और लिथियम जैसे आवश्यक खनिजों के एकाधिकार वाणिज्यिक खनन की अनुमति देता है, जो भविष्य की ऊर्जा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं; कच्चे तेल की खोज सहित खनिज क्षेत्र के भीतर आगे के प्रोत्साहन, विनियमन और निजीकरण को रोकना।

15. आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के विघटन को उलटना और घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना; रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर प्रतिबंधों को बहाल करना; इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को रोकना।
16. कोल भारत लिमिटेड (सीआईएल) के क्षमता विस्तार के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना और एक विस्तृत कोयला रसद ढांचा स्थापित करना; सभी निजी रूप से आवंटित अनछुए कोयला ब्लॉकों को सीआईएल को हस्तांतरित करना; आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना और निजी फर्मों द्वारा धोखाधड़ी वाले कोयला आयात की न्यायिक जांच शुरू करना।

कृषि संस्कृति का पुनरुद्धार

1. कृषि संकट को दूर करने, कृषि विकास को पुनर्जीवित करने और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सीएनपी (आई) निम्नलिखित ठोस कदमों का प्रस्ताव करती है:
2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए एक कानूनी ढांचा सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि यह उत्पादन की व्यापक लागत का कम से कम 1.5 गुना हो (C2 plus 50 percent).
3. एमएसपी के दायरे और निष्पादन को व्यापक बनाना; एमएसपी घोषणाओं के लिए पात्र फसलों की विविधता को बढ़ाना; सभी राज्यों में कुशल खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करना; और तीन साल की समय सीमा के भीतर भारत में कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) की संख्या को बढ़ाकर 10,000 करना।
4. कॉर्पोरेट प्रभाव पर सख्त नियमों को लागू करके और सरकारी सब्सिडी को बढ़ाकर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल, पानी और बिजली जैसे कृषि आदानों की लागत को महत्वपूर्ण रूप से कम करना।
5. सिंचाई और ग्रामीण बाजार के बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर देने के साथ तीन वर्षों में कृषि में सार्वजनिक निवेश को 100% तक बढ़ाना; सभी जल संसाधनों के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) को प्राथमिकता देना।
6. कृषि के लिए संस्थागत ऋण की एक किफायती, समय पर और पर्याप्त आपूर्ति की गारंटी; कॉर्पोरेट हितों के लिए संस्थागत ऋण के डायवर्जन को रोकने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में सुधार; यह सुनिश्चित करने के लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित करें कि प्रत्यक्ष कृषि ऋण का एक महत्वपूर्ण बहुमत छोटे और सीमांत किसानों को आवंटित किया जाए।
7. भारत में सहकारी ऋण प्रणाली को पुनर्जीवित करना; यह सुनिश्चित करना कि ऋण सहकारी समितियाँ नियमित चुनावों के साथ लोकतांत्रिक रूप से काम करें।
8. उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी प्रणाली को समाप्त करना; उचित मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि के लिए सब्सिडी बढ़ाना और उर्वरकों पर मूल्य नियंत्रण बहाल करना।

9. बौद्धिक संपदा ढांचे में संशोधन जो बड़े कृषि निगमों को लाभान्वित करते हैं; बीज मूल्य निर्धारण, रॉयल्टी, बीजों को बचाने के लिए किसानों के अधिकारों और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित निजी कृषि अनुसंधान पर कड़े नियमों को लागू करना।
10. भारत-आसियान एफटीए और भारत-यूरोपीय संघ एफटीए जैसे अनुचित और शोषणकारी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों को निरस्त करना; यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यापार वार्ताएं भारत की आर्थिक संप्रभुता और सहकारी संघवाद को बनाए रखें।

भूमि मुद्दे

सी. एन. पी. (आई) करेगा:

1. मुख्य रूप से निगमों और बड़े कृषि उद्यमों को लाभान्वित करने वाले भूमि-सीमा नियमों के कमजोर होने का पुनर्मूल्यांकन और उलट।
2. भूमि सुधार के लिए त्वरित और संपूर्ण उपायों को लागू करना; राज्य सरकारों को शेष अधिशेष भूमि का अधिग्रहण करने और उन्हें तुरंत वितरित करने के लिए प्रोत्साहित करना, आवंटन प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को प्राथमिकता देना; भूमि स्वामित्व के लिए महिलाओं के समान अधिकारों को बनाए रखने वाले संयुक्त भूमि अधिकार सुनिश्चित करना; कानूनी विवादों के समय पर समाधान के लिए नए भूमि न्यायाधिकरण बनाने के लिए राज्य सरकारों के लिए धन बढ़ाना।
3. सभी किरायेदारों के पंजीकरण की गारंटी दें; सभी राज्यों में किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करें; लाइसेंस प्राप्त कल्टीवेटर कार्ड जारी करने के माध्यम से सब्सिडी, बीमा और आय सहायता सहित किरायेदारों को लाभ दें।
4. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 को संशोधित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी भूमि अधिग्रहण कानूनों पर सार्वभौमिक रूप से लागू हो; सार्वजनिक उद्देश्य की एक सख्त परिभाषा स्थापित करें, सभी प्रभावित व्यक्तियों से पूर्ण और सूचित सहमति की आवश्यकता हो, और व्यापक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और मुआवजे को अनिवार्य करें जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और भूमि के मूल्य में वृद्धि करते हैं।
5. चरागाहों, सामुदायिक वनों और झाड़ियों जैसी सामान्य भूमि के अतिक्रमण और विनियोग को रोकें।
6. सार्वजनिक न्यास में रखी गई सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमि को पट्टे, बिक्री, मोड़ या किसी अन्य माध्यम से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किए जाने से बचाएं।
7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता देते हुए भूमिहीन और गरीब किसान परिवारों को बिना किसी लागत के खेती योग्य बंजर भूमि आवंटित करें; संयुक्त

भूमि अधिकार सुनिश्चित करें जो महिलाओं के भूमि पर समान अधिकारों की पुष्टि करते हैं।

8. ग्रामीण और शहरी भूमिहीन आबादी के सभी वर्गों को आवास स्थल और आवासीय भूमि प्रदान करना।
9. उन सभी राज्यों में किरायेदारी व्यवस्थाओं का दस्तावेजीकरण करें और किरायेदार के अधिकारों की रक्षा करें जहां इस तरह के उपायों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

खाद्य सुरक्षा

भूख मुक्त भारत की दिशा में काम करने के लिए, सीएनपी (आई) करेगा:

1. वर्तमान लक्षित वितरण प्रणाली को बंद करने और एक सुधार, मजबूत सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अधिवक्ता, जो आधार से किसी भी संबंध के बिना आयकर दाताओं को बाहर करता है।
2. प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रावधान सुनिश्चित करें, जिसमें बिना किसी लागत के 5 किलोग्राम और रियायती कीमतों पर अतिरिक्त 5 किलोग्राम शामिल हों।
3. राज्य सरकारों को इस क्षेत्र में पहल करने के लिए प्रोत्साहित करें।
4. खाद्यान्न के अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दलहन, खाद्य तेल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं को विनियमित कीमतों पर उपलब्ध कराएगी।
5. गर्म, पौष्टिक भोजन की गारंटी के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले भोजन के लिए आवंटन में वृद्धि करना और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन प्रावधानों को कानूनी अधिकार के रूप में शामिल करना।
6. गर्भवती महिलाओं के लिए बिना किसी शर्त के 6000 रुपये भत्ते के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान को लागू करें।
7. प्रवासी श्रमिकों, निराश्रितों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों सहित जोखिम वाली आबादी के लिए मुफ्त रसोई जैसी विशेष पहलों को लागू करें।
8. जनजातीय समुदायों और अन्य कमजोर समूहों की खाद्य सुरक्षा तक विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दूरदराज के और पहाड़ी क्षेत्रों में राशन प्रणाली को बढ़ाना।
9. आधार लिंकेज की आवश्यकता के बिना रियायती दरों पर सालाना बारह एलपीजी सिलेंडर प्रदान करें।
10. खाद्यान्न के विकल्प के रूप में नकद हस्तांतरण से बचें।

खाने पीने की कीमत में वृद्धि

सी. एन. पी. (आई) आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव करती है। इनमें शामिल हैं:

1. पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक विनियमित मूल्य निर्धारण प्रणाली को बहाल करना और एक नियंत्रित मूल्य तंत्र को लागू करना।
2. पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क को कम करना।
3. प्राकृतिक गैस और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की कीमतों को विनियमित करना।
4. संसदीय स्थायी समिति की सलाह के अनुसार कृषि वस्तुओं में वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगाना।
5. आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ाते हुए आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त उपाय करना।
6. गोदामों और गोदामों में संग्रहीत निजी खाद्यान्न भंडार के लिए पारदर्शिता आवश्यकताओं में सुधार करना।
7. गोदामों और गोदामों में संग्रहीत निजी खाद्यान्न भंडार के लिए पारदर्शिता आवश्यकताओं में सुधार करना।
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत करना और बाजार की बढ़ती कीमतों का मुकाबला करने के लिए बफर स्टॉक का प्रभावी ढंग से उपयोग करना।
9. उच्च और बढ़ती कीमतों की अवधि के दौरान खाद्यान्न के निर्यात को विनियमित करना।
10. आवश्यक दवाओं की कीमतों का विनियमन सुनिश्चित करना।

विदेशी नीति

CNP (I) का अर्थ है:

1. एक स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के प्रति प्रतिबद्धता जो विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है और बहु-ध्रुवीयता को बढ़ाती है।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक गठबंधन से अलग होने और इसकी हस्तक्षेपवादी नीतियों, प्रतिबंधों और संप्रभु राष्ट्रों में शासन परिवर्तनों को भड़काने के प्रयासों का विरोध करने का निर्णय।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सभी मूलभूत समझौतों से हटने का इरादा जो हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करता है और हमारे हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

4. इजरायल के साथ सभी सुरक्षा और सैन्य साझेदारी की समाप्ति, साथ ही संयुक्त राष्ट्र से इजरायल पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान।
5. 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीन राज्य की मान्यता, जिसमें पूर्वी जेरूसलम को इसकी राजधानी के रूप में नामित किया गया था।
6. पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और साझा संसाधनों से संबंधित मुद्दों को इस तरह से संबोधित करने पर जोर देना जिससे इसमें शामिल सभी पक्षों को लाभ हो।
7. व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देते हुए चीन के साथ सीमा विवाद के समाधान पर बातचीत पर ध्यान केंद्रित करना।
8. पाकिस्तान के साथ चर्चा फिर से शुरू करने का उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद सहित सभी बकाया मुद्दों को हल करना और सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है।
9. उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में शक्तियों के हस्तांतरण की वकालत करने के लिए श्रीलंका सरकार के साथ जुड़ाव, एक एकीकृत राष्ट्र के भीतर तमिल भाषी समुदायों के लिए स्वायत्तता सुनिश्चित करना।

सुरक्षा के मामले

सीएनपी (आई) निम्न के लिए काम करता है:

1. भारत-अमेरिका रक्षा फ्रेमवर्क समझौता, क्राड और आई2यू2 जैसी साझेदारी से वापसी।
2. हमारे क्षेत्र में सभी सैन्य प्रतिष्ठानों को बंद करना, विशेष रूप से हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सुविधा, जहां परमाणु हथियार संग्रहीत किए जाते हैं।
3. परमाणु हथियारों और रासायनिक और जैविक एजेंटों सहित सामूहिक विनाश के सभी प्रकार के हथियारों का पूर्ण उन्मूलन।
4. विश्व स्तर पर सशस्त्र संघर्षों में लगे राष्ट्रों द्वारा ईंधन भरने और तैनात करने के लिए भारतीय नौसेना, वायु और सैन्य सुविधाओं तक पहुंच का निषेध।
5. ऐसी नीति का कार्यान्वयन जो बाहरी अंतरिक्ष और ध्रुवीय क्षेत्रों के सैन्यीकरण को प्रतिबंधित करती है।
6. राजनयिक माध्यमों से विवादों को हल करने, बातचीत और चर्चा को बढ़ावा देने और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता।
7. साइबरस्पेस का असैन्यीकरण; साइबर खतरों और फ़िशिंग से सुरक्षा; व्यक्तिगत गोपनीयता सुनिश्चित करना और अनधिकृत निगरानी को रोकना।

8. जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों पर संसदीय निरीक्षण की स्थापना।
9. खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाकर और विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करके मानव जीवन की सुरक्षा पर जोर।
10. सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों का विस्तार, विकास और सुदृढ़ीकरण, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
11. राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित भ्रष्टाचार के लिए त्वरित जांच, परीक्षण और दंड के साथ भ्रष्टाचार से निपटने के लिए रक्षा अनुबंधों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

जम्मू और कश्मीर

सीएनपी (आई) निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

1. जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए कानून का विशेष प्रावधान और लद्दाख को क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करना; जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का अधिवास भूमि के लिए बिक्री और खरीद समझौते में प्रवेश करने का हकदार नहीं होगा। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विशेष दर्जा दिया जाएगा।
2. जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से 95% नौकरशाही सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का बहुमत शामिल होगा।
3. मुस्लिम अल्पसंख्यकों की धार्मिक मस्जिदों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करना।
4. जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के अधिवासियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुनिश्चित करना, जिसमें व्यापार के नुकसान के मामले में कम प्रावधान हो।
5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी धार्मिक पुजारी/मौलवी राज्य के मुख्यमंत्री की समेकित निधि से मासिक पारिश्रमिक के हकदार होंगे।
6. सभी प्रासंगिक हितधारकों को शामिल करते हुए तेजी से एक राजनीतिक संवाद शुरू करना।
7. विभिन्न सामुदायिक समूहों के साथ जुड़कर और उनकी वैध चिंताओं को दूर करके कश्मीर में विश्वास-निर्माण पहलों को लागू करना।
8. युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत पर विशेष जोर देने के साथ राज्य की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना।
9. सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम का निरसन।

उत्तर-पूर्व

सीएनपी (आई) निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

1. मणिपुर में संघर्ष को हल करने के लिए एक राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है, जिसके लिए वर्तमान मुख्यमंत्री को हटाने की आवश्यकता है। एक समझौते पर पहुंचने के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत में शामिल होना आवश्यक है जो इसमें शामिल सभी समुदायों के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है।
2. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार असम में एनआरसी प्रक्रिया को तुरंत अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। किसी भी भारतीय नागरिक को छूट नहीं दी जानी चाहिए; जिन लोगों को बाहर रखा गया है, उनके पास एक सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया होनी चाहिए, जबकि इसमें शामिल लोगों को बिना किसी देरी के अपने पहचान पत्र प्राप्त करने चाहिए। इसके अलावा, किसी भी अवरुद्ध आधार कार्ड को फिर से मान्य किया जाना चाहिए।
3. पूर्वोत्तर को विकास के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में नामित किया जाना चाहिए, जिसमें भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और युवाओं के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए।
4. विभिन्न जातीय समूहों और राष्ट्रीयताओं की पहचान का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए छठी अनुसूची के तहत दिए गए प्रशासनिक और वित्तीय प्राधिकरणों की सुरक्षा और वृद्धि करना महत्वपूर्ण है।

कामकाजी लोगों और कामकाजी वर्ग के अधिकारों की रक्षा में

CNP (I) का अर्थ है:

1. यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों के लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये प्रति माह से कम न हो, इस मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए। अधिकतम आठ घंटे के कार्य दिवस को लागू करना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार जीवन निर्वाह मजदूरी की गारंटी के लिए विधायी कार्रवाई की जानी चाहिए।
2. सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) के कर्मचारियों के लिए सामर्थ्य से संबंधित किसी भी शर्त को लागू किए बिना नियमित वेतन समायोजन को लागू करना।
3. केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना और जनवरी 2020 से जून 2021 तक बकाया महंगाई भत्ता/महंगाई राहत भुगतान को संबोधित करना।
4. केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न पहलों (जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, एमडीएम कार्यकर्ता, आदि) में लगे सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना। कर्मचारियों के रूप में, इस प्रकार उन्हें वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, पेंशन और उपदान जैसे सामाजिक

सुरक्षा प्रावधानों सहित सभी संबद्ध लाभ प्रदान करना और ट्रेड यूनियन बनाने के उनके अधिकारों की रक्षा करना।

5. चार श्रम संहिताओं में उल्लिखित श्रम कानूनों में उन सभी संशोधनों को निरस्त करना जो श्रमिकों के लिए हानिकारक और नियोक्ताओं के लिए अनुकूल हैं।
6. सभी श्रम कानूनों, विशेष रूप से अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन को बढ़ाना; प्रभावित कर्मचारियों को छंटनी या बंद करने के लिए मुआवजा सुनिश्चित करना; औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करना; श्रम विभागों और प्रवर्तन निकायों को मजबूत करना; और प्रत्येक जिले और औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों की स्थापना।
7. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानून को आगे बढ़ाना और श्रम पर स्थायी समिति की सिफारिशों पर कार्य करना; प्रवासी और बागान श्रमिकों के लिए लक्षित सामाजिक सुरक्षा पहलों को लागू करना; असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कोष बनाना; और सभी असंगठित श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए कानून बनाना, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, प्रसूति और बाल देखभाल के साथ-साथ दुर्घटना और जीवन बीमा के लाभ शामिल हैं।
8. गिग, प्लेटफॉर्म-आधारित और ऐप-संचालित श्रमिकों के साथ-साथ दूरस्थ कार्य में लगे लोगों के लिए काम करने की स्थितियों की स्पष्ट रूप से रूपरेखा तैयार करने के लिए कानून लागू करना। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि आईटी और आईटीईएस कर्मचारी सभी श्रम कानूनों के तहत पूरी तरह से शामिल हैं, जिसमें उचित विधायी उपायों के माध्यम से कोई छूट नहीं दी गई है।
9. नई पेंशन योजना और पी. एफ. आर. डी. ए. अधिनियम को समाप्त करना और एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना की स्थापना करना जो नियोक्ताओं और सरकार दोनों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हो। इस योजना में अनुक्रमण के प्रावधानों के साथ अंतिम वेतन के कम से कम 50 प्रतिशत की पेंशन की गारंटी होनी चाहिए।
10. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019
11. गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियनों की मान्यता सुनिश्चित करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। आई. एल. ओ. सम्मेलन सं. सं. का अनुसमर्थन करने के साथ-साथ सभी प्रतिष्ठानों के लिए संघों को मान्यता देना कानूनी रूप से अनिवार्य होना चाहिए। 87 और 98, जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित हैं, साथ ही साथ नं. 189, जो घरेलू कामगारों को संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय श्रम सम्मेलन बिना किसी अपवाद के प्रतिवर्ष आयोजित किया जाना चाहिए।
12. द्विदलीय और त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हुए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करना। श्रमिक संघों के साथ पूर्व चर्चा किए बिना, श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ नियमित और सार्थक सामाजिक संवाद सुनिश्चित किए बिना श्रम से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।

13. अनुबंध और आकस्मिक श्रम पर निर्भरता को कम करना; अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 को सख्ती से लागू करना; यह सुनिश्चित करना कि अनुबंध श्रमिकों को समान कार्यों को करने के लिए उनके स्थायी समकक्षों के समान मजदूरी और लाभ प्राप्त हों; स्थायी और जारी नौकरियों के आउटसोर्सिंग और अनुबंध को रोकना; निश्चित अवधि के रोजगार को समाप्त करना; और अनुबंध श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र में उन लोगों के संघ बनाने और हड़ताल करने के अधिकारों की रक्षा करना।
14. सभी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, जिसमें घर आधारित काम में लगी महिलाएं भी शामिल हैं; अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें मातृत्व लाभ, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं; 26 सप्ताह की भुगतान मातृत्व अवकाश नीति को लागू करना, साथ ही प्रसूति लाभ, बाल देखभाल सुविधाएं और सभी महिला श्रमिकों के लिए बुजुर्ग देखभाल के लिए समर्थन।
15. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम को सख्ती से लागू करना; रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना।
16. श्रमिकों को उनके लाभ के लिए स्थापित सभी कल्याण बोर्डों में सार्थक और सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।

मछली मजदूर

1. पहचान पत्र जारी करने और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ-साथ मछली श्रमिकों के लिए एक समर्पित कल्याण बोर्ड की स्थापना।
2. बड़े ट्रॉलरों द्वारा नियोजित विदेशी ट्रॉलरों और हानिकारक मछली पकड़ने के तरीकों को प्रतिबंधित करना; गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीतियों को समाप्त करना जो स्थानीय छोटे पैमाने के मछुआरों के लिए पहुंच को सीमित करते हुए हमारे क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं का पक्ष लेती हैं।
3. 2018 की तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना को निरस्त करना, जो मछुआरों के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचने के अधिकारों को कम करता है।
4. नीली अर्थव्यवस्था नीति को त्यागना जो निजी और विदेशी निगमों को हमारे समुद्र तल से मूल्यवान खनिज संसाधनों का दोहन करने की अनुमति देती है।

किसान

1. ग्रामीण भारत में सभी छोटे, मध्यम और व्यथित किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण राहत और ऋण माफी की गारंटी, साहूकारों के लिए संस्थागत और निजी दोनों ऋणों को संबोधित करना।

2. सभी किसानों के लिए एक सार्वभौमिक और समावेशी फसल बीमा कार्यक्रम स्थापित करें, जिससे राज्य-विशिष्ट अनुकूलन की अनुमति मिले; उपज और मूल्य जोखिम दोनों के लिए कवरेज सुनिश्चित करें; प्रत्येक गांव में मौसम निगरानी केंद्र स्थापित करें; फसल बीमा में सार्वजनिक बीमा कंपनियों की भागीदारी बढ़ाएं; और किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाने के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाएं।
3. लघु, सीमांत और मध्यम किसानों के साथ-साथ कृषि श्रमिकों के लिए पर्याप्त मासिक पेंशन के लिए कानूनी आश्वासन प्रदान करना।
4. कृषि उत्पादन, ऋण प्रावधान, डेयरी फार्मिंग, जल प्रबंधन, इनपुट खरीद, फसल भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन पर केंद्रित सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और बढ़ाना; यह सुनिश्चित करना कि बहु-राज्य संस्थाओं को छोड़कर सहकारी समितियां राज्य सरकार के नियमों के तहत काम करें।
5. कृषि उत्पादन में किसान उत्पादक संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त दायित्व समूहों और अन्य महिला समूहों के गठन को प्रोत्साहित करना; यह सुनिश्चित करना कि इन सामूहिक संस्थाओं को निजी कॉर्पोरेट अधिग्रहण से संरक्षित किया जाए।
6. पशु आहार के उत्पादन, आपूर्ति और खुदरा बिक्री के लिए पर्याप्त सब्सिडी सुनिश्चित करें; पशुधन किसानों को इनपुट मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाएं। एक व्यापक पशुधन बीमा कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करें जो सभी बीमारियों और महामारियों को संबोधित करता है।
7. लघु और सीमांत किसानों को मनरेगा के ढांचे में शामिल करके श्रम सब्सिडी का विस्तार करना।

कृषि सांस्कृतिक कार्यकर्ता

1. कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार और पेंशन और दुर्घटना मुआवजे जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों की गारंटी देने के उद्देश्य से व्यापक कानून लागू करना, जो केंद्रीय वित्त पोषण द्वारा समर्थित है।
2. मनरेगा के तहत 100 दिनों के काम की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 200 दिन करना, यह सुनिश्चित करना कि मनरेगा के काम के लिए मजदूरी सभी राज्यों में प्रति दिन 700 रुपये के न्यूनतम वेतन से कम न हो, और काम उपलब्ध न होने पर श्रमिकों के लिए समय पर बेरोजगारी भत्ते की गारंटी देना।
3. सभी ग्रामीण और कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपये प्रति दिन करना, पुरुष और महिला कृषि श्रमिकों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना और गर्भवती श्रमिकों के लिए अतिरिक्त भत्ते प्रदान करना। अधिक प्रभावशीलता और अनुपालन के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन तंत्र में बदलाव करना।

4. यह सुनिश्चित करना कि सभी कृषि श्रमिकों को आवास, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा देखभाल, प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं और चोट से संबंधित घटनाओं के लिए परिवहन सहित आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच हो।
5. प्रवासी कृषि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकल-खिड़की प्रणाली और राष्ट्रव्यापी पात्रता के साथ विकेंद्रीकृत त्रिपक्षीय बोर्डों की स्थापना।
6. एलएआरआर अधिनियम, 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के मामलों में पूर्ण मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्वास के हकदार प्रभावित व्यक्तियों के रूप में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के अधिकारों को स्वीकार करना।
7. दलित और आदिवासी कृषि श्रमिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके समुदायों के व्यापक विकास को बढ़ावा देना।
8. दलित और आदिवासी कृषि श्रमिकों को जाति, जातीयता, धर्म और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए अलग-अलग कानून और न्यायिक प्रणाली बनाना।
9. सभी कृषि कार्यस्थलों में सार्वजनिक रूप से समर्थित बाल देखभाल और शिशुगृह सुविधाओं की स्थापना।

महिलाओं के समान अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए

CNP (I) का अर्थ है:

1. जनगणना और परिसीमन प्रक्रियाओं से स्वतंत्र, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का तत्काल कार्यान्वयन।
2. वैवाहिक और विरासत में मिली संपत्ति में महिलाओं के लिए समान अधिकारों की गारंटी देने वाले कानून की स्थापना; महिलाओं और बच्चों के रखरखाव से संबंधित कानूनों को बढ़ाना; और परित्यक्त सभी महिलाओं के लिए सुरक्षा, पर्याप्त रखरखाव और पुनर्वास सुनिश्चित करना।
3. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा में खतरनाक वृद्धि के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को रोकने, संबोधित करने और दंडित करने के उद्देश्य से उपायों का एक व्यापक सेट पेश करना, जिसमें शामिल हैं:
4. वर्मा समिति की उन सिफारिशों का समर्थन करें जिन्हें वर्तमान संशोधित कानून में शामिल नहीं किया गया है; लैंगिक समानता पर विषयों को शामिल करने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में संशोधन; महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों को लागू करना; यह सुनिश्चित करना कि विकलांग महिलाओं को सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में सुरक्षित पहुंच हो; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को लक्षित करने वाले जाति आधारित अपराधों के लिए दंड में वृद्धि; कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने या देरी करने वाले पुलिस अधिकारियों सहित किसी भी कर्मचारी पर प्रतिबंध लगाना;

फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना; वैवाहिक बलात्कार को अपराधी बनाना; भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए की अखंडता की रक्षा करना; यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक समर्थन प्रदान करना, विशेष रूप से यौन हिंसा से प्रभावित बच्चों के लिए; घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से निपटने वाले कानूनों के प्रवर्तन के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करना। लिंग निर्धारण परीक्षणों और कन्या भ्रूण हत्या का मुकाबला करने और निष्क्रिय निगरानी समितियों को फिर से सक्रिय करने के लिए पी. सी. पी. एन. डी. टी. अधिनियम को सख्ती से लागू करना।

5. नए कानून को लागू करना जिसमें सम्मान अपराधों को संबोधित करने वाला एक समर्पित कानून, महिलाओं और बच्चों की तस्करी को लक्षित करने वाला कानून और महिलाओं और बच्चों के रखरखाव के संबंध में मौजूदा कानूनों में वृद्धि शामिल है। इसमें त्रिपुरा में पूर्व वाम मोर्चा सरकार द्वारा स्थापित पहलों के समान पहल शामिल हो सकती है, जिसने परित्यक्त महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त, विधवाओं और महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों सहित एकल महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम होने चाहिए, साथ ही स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और बैंकिंग संस्थानों के बीच कनेक्शन की सुविधा के लिए कानून होना चाहिए, सब्सिडी वाली ब्याज दरों को 4 प्रतिशत तक सीमित करना सुनिश्चित करना चाहिए, विशेष रूप से एससी/एसटी महिलाओं वाले एसएचजी के लिए लाभ। इसके अलावा, महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों के लिए लक्षित योजनाओं के साथ-साथ घरेलू और घर-आधारित श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक कानून आवश्यक हैं।
6. महिलाओं के संबंध में सम्मानजनक और उपयुक्त सार्वजनिक प्रवचन को बढ़ावा देने के लिए सभी निर्वाचित अधिकारियों के लिए एक आचार संहिता की स्थापना, सेक्सिस्ट और अपमानजनक भाषा को प्रतिबंधित करना जो उनकी गरिमा को कम करता है।
7. जेंडर बजट में महिलाओं के लिए बजटीय आवंटन को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर न्यूनतम चालीस प्रतिशत करना।

बच्चे

CNP (I) दृढ़ता से वकालत करती है और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करेगी। यह प्रतिबद्ध है:

1. आईसीडीएस को सार्वभौमिक रूप से 0-6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शामिल करने के लिए लागू किया जाना चाहिए। आईसीडीएस के संबंध में सभी निजीकरण के प्रयासों को उलट दिया जाना चाहिए, आंगनवाड़ी और स्कूलों में पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रति बच्चे आवंटित धन में वृद्धि के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के भीतर क्रेच सुविधाओं की स्थापना की जानी चाहिए।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विस्तार 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शामिल करने के लिए किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को लागू करना आवश्यक है।

3. स्थानीय पड़ोस में पर्याप्त संख्या में बच्चों के अनुकूल खेल के मैदान स्थापित किए जाने चाहिए।
4. बाल श्रम (निषेध और विनियमन अधिनियम) में संशोधनों से खतरनाक और गैर-खतरनाक कार्यों के बीच के अंतर को समाप्त करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के बाल श्रम को प्रतिबंधित किया जा सके और सभी कामकाजी बच्चों के लिए अधिक धन के साथ पुनर्वास योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
5. आदिवासी, दलित और सामाजिक रूप से कमजोर समूहों और उनके साथियों के बच्चों के बीच की खाई को पाटने के लिए लक्षित उपाय आवश्यक हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस आवासीय स्कूलों और छात्रावासों की स्थापना के लिए अतिरिक्त धन शामिल है।
6. पूरक पोषण, टीकाकरण, गैर-औपचारिक पूर्वस्कूली शिक्षा, नियमित स्वास्थ्य जांच और त्वरित रेफरल सेवाओं सहित आवश्यक सेवाओं के व्यापक कवरेज की आवश्यकता है।
7. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
8. लापता बच्चों का पता लगाने के लिए अधिक प्रभावी उपायों के साथ-साथ सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए आश्रय और सामाजिक सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।
9. किशोर न्याय प्रणाली और इसके संस्थानों में पूरी तरह से बदलाव और सुधार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वे युवा व्यक्तियों को जिम्मेदार नागरिकों के रूप में समाज में फिर से एकीकृत करने में सहायता करने के लिए सुसज्जित हैं।

युवा

CNP (I) निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

1. संवैधानिक अधिकार के रूप में काम करने के अधिकार की स्थापना।
2. रोजगार के अवसरों या बेरोजगारी लाभों का प्रावधान।
3. केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सेवाओं में भर्ती फ्रीज को हटाना; इन सरकारों के भीतर सभी खाली पदों को समय पर भरना सुनिश्चित करना।
4. युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए एक नई राष्ट्रीय युवा नीति बनाना।
5. युवाओं के लिए खेल भागीदारी और प्रशिक्षण संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों प्राधिकरणों द्वारा वित्त पोषित खेल मिशनों की शुरुआत करना।
6. युवा व्यक्तियों के व्यापक विकास-शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-को उनके पसंदीदा क्षेत्रों में अवसर पैदा करके बढ़ावा देना।

7. नशीली दवाओं के संकट से निपटने के लिए निर्णायक उपाय करना।

अनुसूचित कैस्ट और अनुसूचित ट्राइब्स

CNP (I) जाति व्यवस्था और सभी प्रकार के जाति उत्पीड़न के उन्मूलन के लिए खड़ा है।

1. अनुसूचित जातियों और जनजातीय उप-योजना के उद्देश्य से विशेष घटक योजना के लिए एक केंद्रीय कानून की स्थापना, यह सुनिश्चित करते हुए कि राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर योजना आवंटन इन समुदायों की जनसंख्या अनुपात के अनुरूप हो।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक भूमिहीन परिवार को कृषि उद्देश्यों के लिए 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि का प्रावधान।
3. निजी क्षेत्र के भीतर आरक्षण की सुविधा के लिए एक केंद्रीय कानून का निर्माण।
4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 और पी. ओ. ए. संशोधन अधिनियम 2015 के प्रवर्तन को मजबूत करना, संविधान की अनुसूची IX में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पी. ओ. ए.) अधिनियम को शामिल करने की पहल के साथ।
5. एससी, एसटी (पीओए) अधिनियम 1989 की धारा 14 द्वारा अनिवार्य प्रत्येक जिले में अनिवार्य विशेष न्यायालयों की स्थापना।
6. शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों में जाति, धार्मिक और लैंगिक भेदभाव का मुकाबला करने के लिए एक समर्पित कानून की शुरूआत।
7. समग्र जनगणना प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जाति जनगणना का तत्काल निष्पादन।
8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी छात्रों के लिए छात्रावासों और छात्रवृत्ति तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
9. एक केंद्रित, समय-संवेदनशील भर्ती पहल के माध्यम से आरक्षित पदों और पदोन्नति में सभी बकाया रिक्तियों को संबोधित करना।
10. उन क्षेत्रों में आरक्षण का कार्यान्वयन जिन्हें पहले बाहर रखा गया है।
11. मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के उद्देश्य से कानून में अंतराल को खत्म करने के लिए संशोधन, साथ ही पर्याप्त धन द्वारा समर्थित एक समयबद्ध पुनर्वास योजना।
12. स्वच्छता सेवाओं में ठेके पर काम करने वालों को नियमित करना।
13. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों और अन्य लोगों के बीच आवास और नागरिक सुविधाओं में मौजूदा असमानताओं को दूर करने के लिए वित्तीय समर्थन के साथ एक लक्षित पहल।

14. दलित ईसाइयों और मुसलमानों को शामिल करने के लिए आरक्षण नीतियों का विस्तार।

अनुसूचित जनजातियाँ

CNP (I) का अर्थ है:

1. कानून द्वारा अनिवार्य सभी सरकारी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति आरक्षित पदों के लिए उम्मीदवारों की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करना।
2. स्वदेशी समुदायों के भूमि अधिकारों की रक्षा करना और उनसे अवैध रूप से ली गई भूमि को पुनः प्राप्त करना। विभिन्न कानूनों में संशोधन को निरस्त करना, जो व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने की आड़ में, भूमि अधिग्रहण के संबंध में आदिवासी समुदायों के सहमति अधिकारों को कमजोर करते हैं।
3. वन निजीकरण को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय वन नीति को समाप्त करना और इसे आदिवासी अधिकारों को बनाए रखने वाली नीति के साथ बदलना।
4. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 को पूरी तरह से लागू करना, जबकि 1980 की कट-ऑफ तिथि के साथ अन्य पारंपरिक वनवासियों को शामिल करने के लिए इसमें संशोधन करना और यह सुनिश्चित करना कि आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि से बेदखल नहीं किया जाए।
5. आदिवासियों द्वारा एकत्र किए गए लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और आदिवासी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना।
6. वन संरक्षण और पर्यावरण नियमों में उन सभी संशोधनों को निरस्त करना जो अपने-अपने क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के निर्णय लेने के अधिकार को कमजोर करते हैं।
7. जनजातीय भाषाओं और लिपियों की मान्यता, संरक्षण और विकास को बढ़ावा देते हुए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम और पांचवीं अनुसूची के तहत अधिकारों को बनाए रखना। भिली, गोंडी और कोक बोरोक जैसी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को आदिवासी भाषाओं को आधिकारिक राज्य भाषाओं के रूप में मान्यता देनी चाहिए।
8. राज्य सरकारों की अधिवास सूचियों में आदिवासियों को स्वचालित रूप से शामिल करना, यह सुनिश्चित करना कि अंतर-राज्यीय प्रवास की परवाह किए बिना उनकी अनुसूचित जनजाति की पहचान और अधिकारों को मान्यता दी जाए।
9. यह सुनिश्चित करना कि सभी आदिवासी व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किया गया है, उन्हें मुफ्त और सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंच प्रदान करना।

10. जनजातीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सभी जनजातीय छात्रावासों का समय पर ऑडिट करना।

अल्पसंख्याएँ

CNP (I) का अर्थ है:

1. अपने अध्यक्ष और सदस्यों का दर्जा बढ़ाते हुए, विस्तारित प्राधिकरण और अधिकार क्षेत्र के साथ एक वैधानिक इकाई के रूप में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करना।
2. सच्चर समिति की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आदिवासी उप-योजना के आधार पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए एक समर्पित उप-योजना विकसित करना। इसमें महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले जिलों के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में पर्याप्त संसाधन और लक्षित पहल सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक क्षेत्र विकास कार्यक्रम को बढ़ाना और संशोधित करना शामिल है।
3. ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों के प्रति चल रही हिंसा से सुरक्षा के लिए "अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम" पेश करना।
4. रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, राज्य द्वारा विशिष्ट आवंटन के साथ ओबीसी कोटे में मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी ओबीसी मुसलमानों को शामिल करने पर तत्काल ध्यान केंद्रित किया गया।
5. बैंकों से प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण का 15 प्रतिशत विशेष रूप से मुसलमानों के लिए आवंटित करना, साथ ही स्व-नियोजित मुस्लिम युवाओं के लिए रियायती ऋण सुनिश्चित करना।
6. मुस्लिम लड़कियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि करके उनकी शिक्षा पर जोर देना।
7. स्कूलों में उर्दू के निर्देश को प्रोत्साहित करना, उच्च गुणवत्ता वाली उर्दू पाठ्यपुस्तकों का उत्पादन करना और उर्दू शिक्षण पदों में रिक्तियों को संबोधित करना।
8. आतंकवाद से संबंधित मामलों में बरी किए गए सभी मुसलमानों के लिए मुआवजे और पुनर्वास की गारंटी, साथ ही उन अधिकारियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना जिन्होंने उन्हें गलत तरीके से फंसाया और उन्हें यातना दी। इसमें इन मामलों में तेजी लाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना करना शामिल है।
9. मॉब लिंग के सभी पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना।

ओबीसी

1. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रभावी अनुप्रयोग की गारंटी और सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करने के लिए इस आरक्षण का विस्तार करना।
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की क्षमताओं को बढ़ाना।
3. ओबीसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
4. अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए स्थापित पहलों के समान पहलों का एक व्यापक सेट विकसित करना, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसरों में सुधार करना और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के ओबीसी के बीच गरीबी को कम करना है।

एलजीबीटीक्यू +

1. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को संशोधित करना ताकि समुदाय द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का जवाब दिया जा सके।
2. "सिविल यूनियन" या "समलिंगी साझेदारी" जैसे विवाह के समान तंत्रों के माध्यम से समलिंगी जोड़ों के लिए कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करना और तलाक के मामलों में विरासत और गुजारा भत्ता जैसे उद्देश्यों के लिए भागीदारों को आश्रितों के रूप में मान्यता देने की अनुमति देने के लिए 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के समान कानून स्थापित करना।
3. एक व्यापक भेदभाव विरोधी विधेयक पेश करें जिसमें एलजीबीटीक्यू + व्यक्तियों के अधिकार शामिल हों।
4. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नीतियों को लागू करें और रोजगार के अवसरों में क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करें।
5. गारंटी दें कि LGBTQ + व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों पर उसी गंभीरता के साथ मुकदमा चलाया जाता है जैसे गैर-LGBTQ + व्यक्तियों के खिलाफ किया जाता है।
6. शैक्षिक वातावरण में लिंग गैर-अनुरूप और एलजीबीटीक्यू + छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों पर निर्देशित बदमाशी, हिंसा और उत्पीड़न का मुकाबला करने के उपाय स्थापित करें; यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए यूजीसी की संशोधित एंटी-हैरिंग नीति (2016) को लागू करें, और ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और लिंग गैर-अनुरूप व्यक्तियों के लिए सुरक्षित और सुलभ शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

7. सुनिश्चित करें कि एलजीबीटीक्यूआई व्यक्तियों के लिए लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी केवल उनकी सूचित सहमति से की जाती है।

अक्षमताओं वाले लोग

CNP (I) का अर्थ है:

1. विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को एक क्रॉस-कटिंग मुद्दे के रूप में स्वीकार करना; विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों का पुनर्गठन (RPD Act).
2. लैंगिक बजट के संयोजन के साथ विकलांगता बजट का कार्यान्वयन; विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मंत्रालयों में बजट का 5 प्रतिशत आवंटन; आरपीडी अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के निष्पादन का समर्थन करने के लिए धन में वृद्धि।
3. आर. पी. डी. अधिनियम द्वारा अनिवार्य अभिगम्यता प्रावधानों का पालन।
4. सहायक उपकरणों और उपकरणों पर जीएसटी का उन्मूलन।
5. यू. डी. आई. डी. कार्डों को शीघ्र जारी करने और सार्वभौमिक स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
6. निजी क्षेत्र में शैक्षिक और रोजगार आरक्षण का विस्तार; समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को लागू करना।
7. कम से कम रुपये की एक समान विकलांगता पेंशन की स्थापना। 6000/- राज्य में न्यूनतम मजदूरी और रहने की लागत से जुड़ा; एक समकक्ष देखभाल करने वाला भत्ता प्रदान करना; सभी विकलांग व्यक्तियों को एएवाई कार्ड जारी करना; सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यापक और मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करना।
8. आजीविका और आवास को सुरक्षित करने के साथ-साथ अपने यौन और प्रजनन अधिकारों का प्रयोग करने में विकलांग महिलाओं की सहायता करना।
9. "विकलांगता" को भेदभाव के लिए एक निषिद्ध आधार के रूप में शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 को संशोधित करना; विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के प्रावधानों के साथ सभी विधानों को संरेखित करना।

लोगों की भलाई के लिए

CNP (I) निम्नलिखित के लिए काम करेगा:
शिक्षा

1. आई. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निष्पादन को रोकें; शिक्षा के व्यावसायीकरण, सांप्रदायिकरण और केंद्रीकरण को अस्वीकार करें।
2. सार्वजनिक शिक्षा वित्त पोषण के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत आवंटित करें।
3. शैक्षिक सामग्री और पाठ्यपुस्तकों से सांप्रदायिक तत्वों को समाप्त करने के उपाय करें। यह सुनिश्चित करें कि राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में कोई भी कुलपति या प्रमुख अधिकारी धर्मनिरपेक्षता विरोधी विश्वास न रखे।
4. विश्वविद्यालयों, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे संगठनों में नियुक्तियों के लिए अकादमिक उत्कृष्टता और व्यावसायिक योग्यता विशेष मानदंड होंगे। पाठ्यक्रम के सांप्रदायिकरण को संबोधित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा।
5. एक सामान्य स्कूल शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना; सरकारी स्कूलों के बंद होने या विलय को रोकना; केरल मॉडल का पालन करते हुए सरकारी स्कूलों को बढ़ाना; 20:1 के छात्र-शिक्षक अनुपात का लक्ष्य रखना।
6. निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना; पड़ोस की स्कूली शिक्षा को संस्थागत बनाने के लिए आरटीई में संशोधन करना, इसे प्राथमिक स्तरों से आगे बढ़ाना और सभी निरंतर छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना; यह गारंटी देना कि प्रत्येक स्कूल आरटीई मानकों का पालन करता है।
7. ड्रॉपआउट दर को कम करने और इसे सार्वभौमिक बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाना; सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को बढ़ाना, महिला छात्रों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों को बनाए रखने के लिए नियमों और अनुसूचियों में लचीलेपन की अनुमति देना।
8. विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिसरों में यौन उत्पीड़न के खिलाफ लैंगिक संवेदीकरण समितियों की स्थापना करना।
9. निजी शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क, प्रवेश और पाठ्यक्रम की देखरेख के लिए कानून लागू करना।
10. उच्च शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रतिबंधित करना।

11. भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करने वाले सभी शैक्षिक स्तरों पर एक वैज्ञानिक, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम विकसित करें।
12. वर्तमान में अनुबंध के तहत या परा शिक्षकों के रूप में काम करने वाले शिक्षकों की स्थिति को नियमित रोजगार में परिवर्तित करें।
13. सभी शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना; सभी उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों में छात्र संघ के चुनावों को अनिवार्य बनाना।
14. उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता पर किसी भी उल्लंघन को रोकें।
15. एक्सवी। उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाएँ।
16. हाशिए के समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेशी अध्येतावृत्तियां बहाल करें।
17. दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि के छात्रों को सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए रोहित अधिनियम को लागू करें, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाएं और छात्रों के लिए सुलभ सहायता हॉटलाइन शामिल हैं।

स्वास्थ्य

1. राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर उपयुक्त कानून लागू करके मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के अधिकार को न्यायसंगत अधिकार के रूप में स्थापित करना।
2. संघवाद के महत्व पर जोर देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य की जिम्मेदारी के रूप में बनाए रखें।
3. सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक बढ़ाना, यह सुनिश्चित करना कि केंद्र सरकार से कम से कम 2 प्रतिशत आवंटित किया जाए।
4. जेब से निकलने वाले स्वास्थ्य खर्च को कुल स्वास्थ्य खर्च के 25 प्रतिशत से कम करना; स्थानीय समुदायों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए दवाओं, निदान और टीकों की एक व्यापक श्रृंखला सहित सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ाना और मजबूत करना।
5. सरकार द्वारा वित्त पोषित पीएमजेएवाई/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद कर दें और इसे सार्वजनिक-केंद्रित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से बदल दें।
6. सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं और आउटसोर्सिंग के निजीकरण की प्रवृत्ति को उलट दें (PPPs).

7. व्यावसायिक स्वास्थ्य सहित संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों के स्वास्थ्य की प्रभावी ढंग से सुरक्षा के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना का विस्तार और सुधार करना।
8. निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से कॉरपोरेट अस्पतालों को नैदानिक स्थापना अधिनियम के तहत लाकर उनके प्रभावी विनियमन को लागू करना। रोगी अधिकार चार्टर के प्रवर्तन और उचित दरों और सेवाओं की गुणवत्ता के मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए 2010 के राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन करें।
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ संशोधित जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को एकीकृत करके मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक उपचार और देखभाल के लिए अधिकार-आधारित पहुंच की गारंटी।
10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ अद्यतन जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को एकीकृत करके मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक उपचार और देखभाल के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना।
11. एक रोगी-केंद्रित, साक्ष्य-आधारित दवा नीति लागू करें जिसमें प्रभावी लागत नियंत्रण, तर्कहीन और हानिकारक फॉर्मूलेशन को हटाना, और सभी खुदरा दुकानों पर लेबलिंग, पर्चे और उपलब्धता को संबोधित करने वाली एक पूरी जेनेरिक दवा रणनीति शामिल है; सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बिना किसी लागत के आवश्यक दवाओं के प्रावधान की गारंटी।
12. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करने के उद्देश्य से पहल शुरू करें।
13. आवश्यक दवाओं और टीकों के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दवा उद्यमों को पुनर्जीवित करना, निजीकरण की प्रवृत्ति को उलटना; किफायती दवाओं के लिए ओपन-सोर्स ड्रग डिस्कवरी (ओएसडीडी) पहल और सहयोगी अनुसंधान और विकास को बहाल करना; जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं पर जीएसटी को समाप्त करना।
14. नैदानिक परीक्षणों पर कड़े नियमों को लागू करना, अनैतिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करना; नैदानिक परीक्षणों में प्रतिभागियों के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकारों का चार्टर स्थापित करना।
15. भारत के पेटेंट कानूनों को कमजोर होने से बचाएं और मुक्त व्यापार समझौतों के उन खंडों को अस्वीकार करें जो सस्ती जेनेरिक दवाओं के घरेलू उत्पादन में बाधा डालते हैं।
16. इन प्रणालियों के भीतर साक्ष्य-आधारित प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए आयुष चिकित्सा प्रणाली का प्रभावी नियामक निरीक्षण सुनिश्चित करना।

17. स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए नए सार्वजनिक कॉलेजों की स्थापना को प्राथमिकता दें, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और आर्थिक रूप से वंचित राज्यों जैसे कम सेवा वाले क्षेत्रों में; स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान बनाएं।
18. दवाओं के लिए विपणन प्रथाओं पर नैतिक संहिता का अनिवार्य पालन।

रोजगार गारंटी

1. सभी शहरी क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कानून का कार्यान्वयन।
2. मनरेगा कार्यक्रम के तहत 200 दिनों के काम का आश्वासन, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली योग्य गतिविधियों की एक विस्तारित सूची के साथ; ऐप-आधारित उपस्थिति प्रणाली का उन्मूलन।
3. रोजगार सृजन में श्रम-केंद्रित उद्योगों की सहायता के लिए लक्षित पैकेजों की शुरूआत।
4. उन नीतियों के माध्यम से बेरोजगारी का समाधान करें जो श्रम-गहन व्यवसायों को बढ़ावा देती हैं; उन व्यवसायों के भीतर रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं के लिए वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन और रियायतों को जोड़ती हैं।
5. सरकारी एजेंसियों में सभी रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें; भर्ती प्रीज को हटाएं और सरकारी पदों की वार्षिक 3 प्रतिशत कमी; सुनिश्चित करें कि सभी बैकलॉग पद भरे गए हैं।

वरिष्ठ नागरिक

1. वरिष्ठ नागरिकों को गरिमा के साथ जीने के लिए सशक्त बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित, सार्वभौमिक और गैर-योगदानकर्ता वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली की स्थापना आवश्यक है। इस प्रणाली में आयकर दाताओं और अन्य स्रोतों से उच्च पेंशन प्राप्त करने वालों को छोड़कर भारत के सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत पात्रता के रूप में न्यूनतम मजदूरी का कम से कम 50 प्रतिशत या 6,000 रुपये, जो भी अधिक हो, की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी होनी चाहिए।
2. स्वचालित वार्षिक समायोजन सुनिश्चित करने के लिए पेंशन को उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के साथ अनुक्रमित किया जाना चाहिए।
3. वृद्धावस्था पेंशन के प्रसंस्करण के लिए एक सुव्यवस्थित, एकल खिड़की प्रणाली लागू की जानी चाहिए।
4. इसके अतिरिक्त, वृद्धावस्था देखभाल सेवाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्य के समर्थन से वृद्धाश्रमों, डे-केयर केंद्रों और उपशामक देखभाल सुविधाओं का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिक

1. वन रैंक, वन पेंशन नीति को व्यापक रूप से लागू करना; सैन्य कर्मियों के लिए दुर्घटना पेंशन और विकलांगता मुआवजे के लिए अद्यतन नियमों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।
2. सेवानिवृत्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सदस्यों, उनकी विधवाओं और आश्रितों के हितों की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि उन्हें सशस्त्र बलों के समान व्यवहार मिले।
3. पूर्व सैनिकों की चिंताओं और चुनौतियों से निपटने के लिए एक पूर्व सशस्त्र बल अधिकारी के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों के लिए एक आयोग की स्थापना करना।

यूआरबीएन मुद्दे

तेजी से हो रहे शहरीकरण और असमान विकास के आलोक में, सीएनपी (आई) निम्नलिखित पहलों के लिए समर्पित है:

1. शहरी परिवेशों में अनौपचारिक और असंगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए लक्षित उपायों को लागू करना।
2. पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण का विरोध करना।
3. बेदखली अभियानों को रोकना और झुगियों को ध्वस्त करना, साथ ही आवश्यक सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देना।
4. सार्वजनिक आवास विकल्पों, सार्वजनिक परिवहन और हरित स्थानों को बढ़ाना।
5. सभी प्रकार के प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के लिए कार्रवाई करना।
6. एक नई शहरी नीति की वकालत करना जो निजी अचल संपत्ति के हितों पर आम जनता के कल्याण पर जोर देती है।
7. 74 वें संविधान संशोधन को मजबूत करके शहरी स्थानीय निकायों को अधिकार के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना।
8. यह सुनिश्चित करना कि शहरी स्थानीय निकायों को सभी निवासियों के लिए उचित आवास, पानी और स्वच्छता सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्राप्त हों।

पर्यावरण

1. राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण मंजूरी प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता, समयबद्धता, पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता को बढ़ाना; ईआईए अधिसूचना 2020 को रद्द करना और अद्यतन दिशानिर्देशों को लागू करना।
2. सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देते हुए जीवाश्म ईंधन से उचित संक्रमण सुनिश्चित करते हुए ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में व्यापक उपायों का विकास और कार्यान्वयन करना।
3. एक समावेशी प्रक्रिया के माध्यम से एक राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (एनएपी) बनाएं जो कृषि पर प्रभाव, अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन, शहरी बाढ़, गर्मी की लहरों, शहरी गर्मी द्वीपों, तटीय कटाव और समुद्र के बढ़ते स्तर सहित जलवायु संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्य सरकारों को शामिल करती है।
4. कमजोर हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाटों और पूर्वोत्तर के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल विकास रणनीतियाँ तैयार करना।
5. शहरी वायु प्रदूषण में तेजी से और लक्षित कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का व्यापक संशोधन करना।
6. नदी के तल और बाढ़ के मैदानों के क्षरण और हानिकारक विकास को रोकने के लिए रणनीतियों को तुरंत लागू करें, विशेष रूप से शहरी सेटिंग्स में।
7. जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों को निरस्त करना जो जैव विविधता संसाधनों के बारे में ज्ञान को कॉर्पोरेट संस्थाओं को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है।
8. अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप श्रृंखलाओं के लिए पर्यावरणीय रूप से हानिकारक और कॉर्पोरेट-अनुकूल द्वीप विकास योजना को छोड़ दें; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित नौसैनिक अड्डे की व्यवहार्यता और स्थान का पुनर्मूल्यांकन करें।
9. पर्यावरणीय रूप से हानिकारक राष्ट्रीय तेल पाम मिशन को बंद कर दें, जो उत्तर-पूर्व और अंडमान द्वीप समूह में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में उपज और लक्ष्य के बारे में अतिरंजित दावे करता है।

जल संसाधन

1. जल को एक सीमित सार्वजनिक संसाधन के रूप में मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय जल नीति को संशोधित करना; बढ़ते जल संकट को दूर करना; नदियों की प्रभावी रूप से सुरक्षा,

जल निकायों का विस्तार और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाकर घरेलू उपयोग, कृषि और उद्योग के लिए पानी की उचित पहुंच को बढ़ावा देना। इसमें विशेष रूप से शहरी परिवेशों में जल लेखा परीक्षा आयोजित करने और संरक्षण, उपचार और पुनर्चक्रण प्रथाओं को अपनाने के साथ-साथ उपयुक्त कानून स्थापित करना, मजबूत नियमों को लागू करना और पानी की मांग का प्रबंधन करना शामिल है।

2. यह सुनिश्चित करें कि सभी घरों को पाइप से पीने का पानी मिले जो डब्ल्यूएचओ के मानकों को पूरा करता हो।
3. शहरी क्षेत्रों में जल संसाधनों और वितरण सेवाओं के निजीकरण को रोकें, जीवन के अधिकार के एक अनिवार्य घटक के रूप में पानी के अधिकार की पुष्टि करें।
4. नदियों और अन्य जल निकायों में प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए कड़े कानून, विनियमन और अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण नीतियों को लागू करना; जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन, 2024 के प्रावधानों को निरस्त करना जो केंद्र को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को ओवरराइड करने की अनुमति देता है (SPCBs).
5. नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम का गहन मूल्यांकन करना।
6. प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों की रक्षा करने और बढ़ाने के लिए रणनीतियों को लागू करें, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में, और ग्लेशियर के पिघलने को कम करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

1. मौलिक अनुसंधान को प्राथमिकता देते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भीतर स्वदेशी अनुसंधान में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के न्यूनतम 2 प्रतिशत तक बढ़ाना।
2. विश्वविद्यालय अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) ढांचे को बढ़ाना; अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की उपलब्धता का विस्तार करना; संस्थानों में संकाय अनुसंधान भूमिकाओं की संख्या को बढ़ावा देना; और पीएचडी कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार करना।
3. अनुसंधान वित्त पोषण प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विकेंद्रीकरण करना; राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थापित अत्यधिक केंद्रीकृत राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) को समाप्त करना। (NEP).
4. सरकार द्वारा वित्त पोषित कई विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों को बंद करने के निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करें; पुनर्गठित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के लिए सरकारी समर्थन को बहाल करें।

5. सूखा, जल संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आजीविका और हाशिए के समूहों को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसी सामुदायिक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से राज्य-स्तरीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलों के लिए धन आवंटित करें।
6. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और जैव प्रौद्योगिकी सहित चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवश्यक मिशन-संचालित अनुसंधान और विकास वित्त पोषण प्रदान करना, जबकि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा आयोजित एकाधिकार का मुकाबला करने और जलवायु को बढ़ावा देने के लिए कृषि अनुसंधान पर भी जोर देना-लचीला कृषि और बागवानी।
7. एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्रों और पदों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यवस्थित रणनीतियों को लागू करना; ब्रेन ड्रेन को कम करने के लिए अकादमिक स्वतंत्रता और अनुसंधान संस्कृति के वातावरण को बढ़ावा देना।
8. सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए एआई, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, डेटा माइनिंग और आईटी-आधारित निगरानी के लिए नियम स्थापित करें।
9. संवैधानिक निर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक मानसिकता, जांच की भावना और सुधार को बढ़ावा देना; विज्ञान को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक मानसिकता को विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार निकाय के साथ विज्ञान प्रसार को पुनर्जीवित करना।
10. मुक्त और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए अधिवक्ता जो कॉपीराइट या पेटेंट के माध्यम से एकाधिकारवादी नियंत्रण के अधीन नहीं हैं; जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दवा की खोज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में "नॉलेज कॉमन्स" के विकास को प्रोत्साहित करें।
11. डिजिटल बुनियादी ढांचे को समाज के लाभ के लिए एक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में स्वीकार करें।
12. सार्वजनिक संचार नेटवर्क को बढ़ाने और वैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रकाशनों तक अप्रतिबंधित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का आवंटन, कॉपीराइट बाधाओं को समाप्त करना; यह आवश्यक है कि सार्वजनिक धन द्वारा वित्त पोषित सभी शोध जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएं।

निगरानी और गोपनीयता के मुद्दे

1. राज्य एजेंसियों द्वारा संचालित सभी प्रकार की डिजिटल निगरानी को तब तक बंद कर दें जब तक कि कड़े न्यायिक निरीक्षण के साथ स्पष्ट और विशिष्ट वारंट न हों। नागरिकों के फोन, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए मैलवेयर, हैकिंग या पेगासस जैसी अन्य आक्रामक तकनीकों की तैनाती को रोकें।

2. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023) को निरस्त करें, जिसका उद्देश्य राज्य एजेंसियों को नागरिकों पर व्यापक निगरानी शक्तियां प्रदान करके और बड़े निगमों को लाभ के लिए नागरिकों के डेटा का शोषण करने की अनुमति देकर डिजिटल अधिनायकवाद को बढ़ाना है।
3. निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हुए, एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करने के लिए नया कानून बनाना जो सर्वोच्च न्यायालय के पुट्टुस्वामी फैसले के साथ संरेखित हो। इसके अतिरिक्त, सरकारी संस्थाओं और निजी कंपनियों दोनों द्वारा नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन की निगरानी और समाधान के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण बनाएँ।
4. दूरसंचार और डिजिटल एकाधिकार के प्रभाव को प्रभावी ढंग से विनियमित करने और सीमित करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की क्षमताओं को बढ़ाना।
5. निगरानी और अवरोधन, इंटरनेट शटडाउन, एन्क्रिप्टेड सेवाओं को कम करने और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं पर लगाए गए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) आवश्यकताओं से संबंधित दूरसंचार अधिनियम 2023 के दमनकारी प्रावधानों को रद्द करें।
6. कड़े आई. टी. संशोधन नियम (2023) को समाप्त करें जो ऑनलाइन असहमति को दबाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के विवेकाधिकार पर एक तथ्य-जांच इकाई की स्थापना के माध्यम से सरकार को व्यापक सेंसरशिप शक्तियां प्रदान करते हैं।

संस्कृति और मीडिया

1. संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को हिंदी लागू किए बिना समान प्रोत्साहन और विकास मिलना चाहिए।
2. एक धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिबद्धता आवश्यक है; सांस्कृतिक हस्तियों और सांप्रदायिक ताकतों द्वारा कार्यों पर किसी भी हमले को निर्णायक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।
3. हिंसा के महिमामंडन और महिलाओं और कामुकता के कमोडिटीकरण को रोकने के लिए एक ठोस प्रयास होना चाहिए।
4. इंटरनेट शासन को U.S. नियंत्रण से एक उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण में परिवर्तित किया जाना चाहिए, एक जन-केंद्रित इंटरनेट को बढ़ावा देना जो सामाजिक न्याय पर जोर देता है और वैश्विक निगमों के प्रभाव से मुक्त है; गोपनीयता अधिकारों की रक्षा करने और सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर निगरानी को रोकने के लिए एक वैश्विक इंटरनेट ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए।
5. फर्जी खबरों के प्रसार का मुकाबला करने और इसका प्रचार करने वाले व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

6. पत्रकारों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने और दुर्भावनापूर्ण कानूनी कार्रवाइयों से बचाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
7. सूचना के मुक्त प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए सहकारी और सामूहिक मीडिया संगठनों के लिए समर्थन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए; प्रसार भारती निगम को एक सच्ची सार्वजनिक प्रसारण सेवा के रूप में कार्य करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।
8. एकाधिकार प्रथाओं और सहयोगी कंपनियों द्वारा मीडिया के नियंत्रण को रोकने के लिए क्रॉस-मीडिया स्वामित्व पर नियम स्थापित किए जाने चाहिए; प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
9. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को शामिल करते हुए एक एकीकृत मीडिया परिषद का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें मीडिया क्षेत्र, मीडिया संघों और स्वतंत्र सार्वजनिक हस्तियों के प्रतिनिधि शामिल हों; वैश्वीकरण शुरू होने के बाद से पत्रकारों की खराब कामकाजी परिस्थितियों और मीडिया में विकसित रुझानों की जांच के लिए एक मीडिया आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
10. कामकाजी पत्रकार अधिनियम को बहाल किया जाना चाहिए और सभी मीडिया प्लेटफार्मों-प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक में पत्रकारों और श्रमिकों को कवर करने के लिए उचित मजदूरी और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे मजबूत किया जाना चाहिए; मीडिया संगठनों के भीतर मुआवजे की समीक्षा और समायोजन के लिए इन क्षेत्रों में पत्रकारों के लिए एक नया वेतन बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
11. 2021 में आईटी नियमों में किए गए संशोधनों को रद्द कर दिया जाएगा और प्रस्तावित प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2022 की समीक्षा की जाएगी। हालांकि, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम की जगह लेने वाले प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 के मसौदे को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

संस्थागत सुधारों के लिए

CNP (I) का अर्थ है:

1. भाषण, अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत अधिकारों की स्वतंत्रता पर अनुचित सीमाएं लगाने वाले किसी भी प्रावधान की समीक्षा और सुधार करते समय व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना।
2. सीवीसी, सीबीआई, ईसीआई, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकपाल, लोकायुक्ता और महिला और एससी/एसटी आयोगों जैसे निरीक्षण, नियामक और न्यायिक संस्थानों के लिए नियुक्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देकर वैधानिक, संवैधानिक और नियामक निकायों की स्वायत्तता को बनाए रखना। इसमें भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और रोकने के उपायों को लागू करना शामिल है, विशेष रूप से उच्च स्तरों पर; शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना; व्हिसलब्लोअर की रक्षा करना;

न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना जो तेज और किफायती दोनों हो; और चुनावी प्रणाली में सुधार करना।

भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और जवाबदेही बढ़ाना

1. पिछले चार वर्षों में इसके संचालन से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए, लोकपाल संस्थान को बढ़ाने और कार्यपालिका से इसकी स्वायत्तता की गारंटी देने के उपाय।
2. निगमित कदाचार की व्यापक जांच करने के लिए नियामक निकायों और जांच एजेंसियों को सशक्त बनाना।
3. यह सुनिश्चित करना कि निजी वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल, लोकपाल अधिनियम, व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम और अन्य प्रासंगिक भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
4. आर. टी. आई. उपयोगकर्ताओं और भ्रष्टाचार विरोधी अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करना, इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम में संशोधन करना।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम को मजबूत करना और शासन के निर्णयों में नागरिकों की भागीदारी के लिए संरचित रास्ते बनाना; एक पारदर्शी और सहभागी पूर्व-विधायी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 4 को लागू करना जो कानूनों के अधिनियमन से पहले सार्वजनिक इनपुट को आमंत्रित करता है
6. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) के दुरुपयोग को संबोधित करना और आवश्यक सुधारों को लागू करना।

न्यायिक सुधार

1. एक स्वतंत्र संवैधानिक इकाई के रूप में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना जिसमें नियुक्तियों, स्थानांतरणों की देखरेख करने और न्यायिक कदाचार के मामलों की जांच करने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और बार के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिससे न्यायपालिका के भीतर जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
2. न्यायपालिका के भीतर मौजूदा रिक्तियों को संबोधित करते हुए आम जनता के लिए न्याय तक त्वरित और किफायती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रणाली में बदलाव करना।
3. असहमति को दबाने के लिए एक उपकरण के रूप में इसके संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए आपराधिक अवमानना की परिभाषा में उचित संशोधन करना।

4. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति के सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य करना।
5. सभी स्तरों पर न्यायपालिका के भीतर पर्याप्त प्रतिनिधित्व और विविधता को बढ़ावा देना।

निर्वाचन आयोग में सुधार

1. 2023 के 'सीईसी और अन्य ईसी (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम' को संशोधित करना ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिशों के आधार पर चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।
2. चुनाव आयुक्तों को कानूनी रूप से सरकार में किसी भी पद पर रहने, राज्यपाल के रूप में कार्य करने या उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किसी विधायी निकाय का सदस्य होने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
3. चुनाव पर्यवेक्षकों के अधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करें।

विद्युत सुधार

1. आंशिक सूची दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत।
2. आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए संसाधनों के रूप में राज्य वित्त पोषण का प्रावधान, इन दलों के लिए कॉर्पोरेट योगदान पर प्रतिबंध के साथ।
3. लोकतंत्र में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन करना आवश्यक है (EVMs). इसमें मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों को फिर से व्यवस्थित करना शामिल है-विशेष रूप से, मतदान इकाइयाँ, नियंत्रण इकाइयाँ और वीवीपीएटी। परिणामों की घोषणा से पहले नियंत्रण इकाई में दर्ज डेटा के खिलाफ कम से कम 50 प्रतिशत वीवीपीएटी का सत्यापन किया जाना चाहिए।
4. चुनावी वित्तीय प्रथाओं में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, व्यक्तिगत उम्मीदवारों पर लगाए गए खर्च की सीमा के समान राजनीतिक दलों के लिए एक खर्च सीमा स्थापित करें।

